भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 175
बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 (6 अग्रहायण, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य सुरक्षा

175 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम के तहत चलाई गई प्रायोगिक परियोजना की स्थिति और उपलब्धि क्या है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य- वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस कार्यक्रम के तहत उपयुक्त शीतागार सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस प्रायोगिक परियोजना के बाद, राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए किन पहलों पर विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त कार्यक्रम के तहत हरियाणा में कितने गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि के निर्माण का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेज़ (नैबकॉन्स) की सहायता से, 11 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण **अनुलग्नक- I** पर संलग्न है ।

योजना के तहत, पैक्स एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत गांवों में उत्पादित फलों और सब्जियों की आपूर्ति के लिए शीतागारों, पैक हाउस, प्रशीतन वैन आदि सहित कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित कर सकती है ।

पायलट परियोजना का विस्तार कर दिया गया है और संपूर्ण देश में दिनांक 21.11.2024 तक 500 से अधिक अतिरिक्त पैक्स को चिह्नित किया गया है । इसका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है।

(घ): हरियाणा राज्य ने परियोजना में भाग लेने के इच्छुक 11 पैक्स को चिह्नित किया गया है, जिनका जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**जिले का नाम**	**चिह्नित किए गए पैक्स**
1.	पंचकुला	3
2.	नूहं	7
3.	चरखी दादरी	1

****

अनुलग्नक -I

पायलट परियोजना की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	पैक्स का नाम	जिला	राज्य	गोदाम क्षमता (मीट्रिक टन में)
1.	नेरीपांगलई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	अमरावती	महाराष्ट्र	3,000
2.	बहुदेशीय प्रथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडे	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	1,500
3.	दी चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	अहमदाबाद	गुजरात	750
4.	घमुडवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	श्री गंगानगर	राजस्थान	250
5.	बहुदेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्यादित पार्सवाड़ा	बालाघाट	मध्य प्रदेश	500
6.	बहुदेशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर	देहरादून	उत्तराखंड	500
7.	सिलामराथुपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी	थेनी	तमिलनाडु	1,000
8.	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड गंभीरावपेट	करीमनगर	तेलंगाना	500
9.	2 नं. पब बोंगशर जी.पी.एस.एस लिमिटेड	कामरूप	असम	500
10.	प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एकम्बा	बीदर	कर्नाटक	1,000
11.	खिलपारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	गोमती	त्रिपुरा	250

पायलट परियोजना के अंतर्गत देश के 11 राज्यों में कुल 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है।

अनुलग्नक -II

पायलट परियोजना के विस्तार का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	चिह्नित किए गए पैक्स
1.	ओडिशा	79
2.	उत्तर प्रदेश	24
3.	महाराष्ट्र	258
4.	मध्य प्रदेश	38
5.	त्रिपुरा	8
6.	गुजरात	47
7.	हरियाणा	11
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	राजस्थान	100
10.	कर्नाटक	32
कुल		**599**